नईदुनिया

इजरायल-लेबनान शांति समझौते पर हिजबुल्लाह ने दी गृहयुद्ध की चेतावनी

बेरुत

अमेरिका की मध्यस्थता से इजरायल और लेबनान के बीच एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करना, लेबनानी सरकार की संप्रभुता को बहाल करना और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना है। हालांकि, इस पहल ने क्षेत्र में शांति की उम्मीदों के साथ-साथ गंभीर तनाव की आशंका भी पैदा कर दी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इसे सिरे से खारिज करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इसे लागू करने का प्रयास किया गया तो लेबनान गृहयुद्ध की ओर बढ़ सकता है।

वाशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मौजूदगी में हुए इस समझौते को दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की दिशा में एक अहम कदम बताया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, यह फ्रेमवर्क हिजबुल्लाह के हथियारबंद ढांचे को समाप्त करने, इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी और लेबनानी सरकार की संप्रभुता की बहाली के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। समझौते को लागू करने के लिए अमेरिका मिलिट्री कोआर्डिनेशन ग्रुप फार लेबनान नामक एक नया तंत्र बनाएगा और साथ ही लेबनान के लिए 10 करोड़ डालर की मानवीय सहायता देने की भी घोषणा की गई है। समझौते पर अमेरिका में इजरायल के राजदूत येचिएल लेइटर और लेबनान की राजदूत नादा हमादेह मोआवद ने हस्ताक्षर किए। इजरायली राजदूत ने कहा कि उनका अंतिम लक्ष्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना है, जहां भविष्य में तेल अवीव से लोग बेरूत तक बिना किसी डर के यात्रा कर सकें और लेबनान के नागरिक भी इजरायल आ-जा सकें, लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह तभी संभव होगा जब हिजबुल्लाह अपने हथियार पूरी तरह छोड़ देगा और उसका सैन्य ढांचा समाप्त हो जाएगा। वहीं लेबनानी राजदूत ने इस समझौते को देश की संप्रभुता बहाल करने, इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करने और विस्थापित लोगों की घर वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उनका कहना था कि यह स्थायी युद्धविराम और क्षेत्र में शांति स्थापित करने की शुरुआत है। इसके विपरीत, हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन के सांसद हसन फदलल्लाह ने स्पष्ट किया कि हिजबुल्लाह अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं त्यागेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन से लेबनान पर थोपा जा रहा यह समझौता देश को गृहयुद्ध की ओर धकेल सकता है, खासकर यदि लेबनानी सरकार इसे अपने ही नागरिकों के खिलाफ टकराव के रास्ते से लागू करने का प्रयास करती है। मौजूदा संघर्ष उस समय शुरू हुआ था जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में उत्तरी इजरायल पर राकेट दाग दिए। इसके जवाब में इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में सैन्य अभियान तेज कर दिया, जिसमें मार्च से अब तक लेबनान में इजरायली हमलों में चार हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इजरायल के भी कई सैनिक मारे गए हैं।

न्यूज ब्रीफ

पाकिस्तान में भूकंप के तेज झटके 5.4 की तीव्रता से हिली धरती

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5.4 तीव्रता के तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे कुछ ही समय पहले वेनेजुएला में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसने वैश्विक स्तर पर भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि का संकेत दिया। यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलाजिकल सेंटर (ईएमएससी) और अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीसी) की प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान के बरखान शहर से लगभग 63 किलोमीटर दूर जमीन से 35 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। हालांकि, कुछ अन्य स्रोतों ने इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई है, जिससे सटीक गहराई को लेकर थोड़ी भिन्नता है। भारतीय समयानुसार यह भूकंप सुबह करीब 8:36 बजे आया, जिसके झटके महसूस होते ही कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों और अन्य इमारतों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर निकल आए। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अचानक आए इन झटकों ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। फिलहाल, यह राहत की बात है कि अभी तक किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान या किसी बड़े बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंचने की कोई तत्काल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं। वे सुदूर ग्रामीण इलाकों से भी भूकंप के प्रभावों का आकलन जुटाने में लगे हैं, ताकि किसी भी अप्रत्याशित घटना या नुकसान का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके। पाकिस्तान भूगर्भीय रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यह देश एक ऐसी महत्वपूर्ण सीमा रेखा पर स्थित है, जहां शक्तिशाली इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराती हैं। इस भूगर्भीय टकराव के कारण यहां अक्सर भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत विशेष रूप से फाल्ट लाइनों के बेहद करीब होने के कारण इन भूकंपीय झटकों की चपेट में आते रहते हैं।

पापुआ न्यू गिनी में मिली चलती शार्क की अनोखी प्रजाति

लंदन। शार्क का नाम सुनते ही दिमाग में समुद्र के खतरनाक शिकारी की तस्वीर आती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी शार्क की पहचान की है जो तैरने के साथ-साथ चल भी सकती है। पापुआ न्यू गिनी में मिली इस नई प्रजाति को वाकिंग शार्क कहा जा रहा है, जो अपने पेक्टोरल फिन (सामने वाले पंख) का इस्तेमाल पैरों की तरह करती है और कम पानी व कोरल रीफ के ऊपर आसानी से चलती है। पापुआ न्यू गिनी के मिल्ने बे क्षेत्र के लोग इस काडेडेकेडेवा (डाग शार्क या आलसी शार्क) के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों ने अब इसकी औपचारिक पहचान कर नई प्रजाति घोषित किया है। यह शार्क हेमीसीलियम जीनस का हिस्सा है। इस समूह की अब तक 9 प्रजातियां दर्ज थीं, जो अब बढ़कर 10 हो गई हैं। नई प्रजाति का नाम हेमिसाइलियम डडजोने रखा गया है, जो आस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिस्टीन डजियन के सम्मान में है। मार्च 2025 में वैज्ञानिकों की एक टीम मिल्ने बे में सर्वे कर रही थी, जब उन्हें लगभग एक मीटर गहरे पानी में यह अनोखी शार्क मिली। शुरुआत में टीम किसी और प्रजाति की तलाश में थी, लेकिन इस शार्क का रंग और शरीर पर बने छोटे डैश-जैसे निशान बाकी वाकिंग शार्क से अलग थे।

अमेरिका में 4.5 लाख प्रवासी बच्चे लापता, गृह सुरक्षा विभाग चिंतित तलाशी अभियान तेज

वाशिंगटन। अमेरिका के गृह सुरक्षा सचिव मार्कवेन मुलिन ने बताया है कि उनका विभाग उन 4.5 लाख प्रवासी बच्चों का पता लगाने में जुटा है, जिनका पिछली सरकार के दौरान प्रायोजकों के पास भेजने के बाद संपर्क टूट गया था। अब तक इसमें से 1.47 लाख बच्चों का पता लग चुका है। गृह सुरक्षा से जुड़े मामलों पर हाउस एप्रोप्रिएशन सब-कमेटी के समक्ष गवाही देकर मुलिन ने कहा कि कमजोर और असुरक्षित प्रवासी बच्चों का पता लगाना गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुलिन ने स्पष्ट किया कि जिन बच्चों का पता चला, उनमें से सभी किसी खतरे की स्थिति में नहीं थे, कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुरक्षित मिले।

सीजफायर तोड़ा तो भड़के ट्रंप, ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले, 500 से अधिक जहाज होर्मुज में फंसे

वाशिंगटन

मिडिल ईस्ट में एक हफ्ता पहले ही संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन यह सहमति चंद दिनों में ही टूटती दिख रही है। पहले ईरान ने स्ट्रेट आफ होर्मुज में जहाजों पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार, 26 जून को ओमान तट के पास एक मालवाहक जहाज पर हुए ड्रोन हमले का जवाब दिया और ईरान के भीतर कई सैन्य ठिकानों पर भीषण जवाबी हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन केंद्रों के साथ-साथ तटीय रडार साइटों को निशाना बनाया है, जिसकी पुष्टि स्वयं अमेरिकी अधिकारियों ने की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की इस हरकत को सीजफायर समझौते का मूर्खतापूर्ण उल्लंघन करार दिया है और कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।

25 जून को सिंगापुर के झंडे वाले एक बड़े मालवाहक जहाज पर ओमान तट के पास स्ट्रेट आफ होर्मुज से बाहर निकलते समय ईरान द्वारा आत्मघाती ड्रोन दागे गए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, इस जहाज को निशाना बनाकर कुल चार ड्रोन दागे गए थे, जिनमें से तीन को अमेरिकी सेना ने हवा में ही मार गिराया। हालांकि, एक ड्रोन जहाज के ऊपरी डेक पर जा टकराया, जिससे जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सेना ने भी इस हमले की पुष्टि की है, लेकिन राहत की बात यह रही कि हमले में किसी भी नाविक के हताहत होने की खबर नहीं है। इस उकसावे वाले हमले के ठीक एक दिन बाद, अमेरिकी विमानों ने ईरानी सीमा के भीतर घुसकर उसके ड्रोन और मिसाइल डिपो को तबाह कर दिया। सेंटकाम ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी बयान में कहा, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जहाज पर कल हुए हमले के एक शक्तिशाली जवाब के रूप में ईरान के खिलाफ हवाई हमले किए हैं। ईरानी सैनिकों द्वारा जहाजों पर किया गया यह बिना वजह का हमला सीधे तौर पर युद्धविराम का उल्लंघन है। इस ताजा गोलाबारी के बाद अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) ने फारस की खाड़ी से फंसे हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के अपने अभियान को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। आईएमओ के महानिदेशक आर्सेनियो डोमिंगुएज ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में

वैकल्पिक मार्ग से करीब 115 जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन इस हमले के बाद अभी भी लगभग 500 व्यापारिक जहाज इसी अशांत क्षेत्र में फंसे हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि जब तक सुरक्षा की पुख्ता गारंटी नहीं मिलती, रेस्क्यू आपरेशन दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा, जिससे वैश्विक व्यापार पर गंभीर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, ईरान समर्थित पर्शियन गल्फ स्टेट अथारिटी ने हमले से कुछ घंटे पहले ही चेतावनी जारी की थी कि जो भी जहाज उनके द्वारा तय किए गए स्वीकृत रूटों के बाहर से गुजरेगा, उसे कोई सुरक्षा या बीमा कवर नहीं दिया जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी जहाज के कमांडर की होगी।

कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में 60 फीसदी की भारी गिरावट

टोरंटो। कनाडा में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों के आकर्षण में इस साल ऐतिहासिक गिरावट दर्ज हुई है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (आईआरसीसी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष देश में आने वाले विदेशी छात्रों की कुल संख्या में 60 प्रतिशत की भारी कमी आई है, जिसमें एक लाख पचास हजार से अधिक छात्रों की कमी दर्ज हुई है। इस गिरावट पर देश के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मुहर लगाकर कहा कि उनकी सरकार ने इमिग्रेशन प्रणाली पर पुनः पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। सरकार का उद्देश्य एक अधिक टिकाऊ, पारदर्शी और भरोसेमंद आव्रजन व्यवस्था का निर्माण करना है जो कनाडाई मूल्यों के अनुकूल हो। प्रधानमंत्री के अनुसार, नए सुधारों के बाद शरणार्थियों के दावों में एक-तिहाई और अस्थायी विदेशी कामगारों की संख्या में भी लगभग आधी कटौती की गई है। कनाडा सरकार द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों का सबसे बड़ा असर भारतीय छात्रों पर पड़ा है, जो कभी वहां के सबसे बड़े छात्र समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। साल 2023 में कनाडा के कुल अंतरराष्ट्रीय छात्रों में भारतीयों की हिस्सेदारी 51.6 प्रतिशत थी, जो अब सिमटकर महज 8.1 प्रतिशत रहा है। इस भारी गिरावट के पीछे स्टडी परमिट के नियमों में अत्यधिक सख्ती, बढ़े हुए वित्तीय मानदंड और पोस्ट-ग्रेजुएशन वर्क परमिट (पीजीडब्ल्यूपी) के कड़े नियम प्रमुख कारण हैं।

जहरीले सांपों के लिए सीधे मौत का पर्याय है सेक्रेटरी बर्ड पक्षी

सवाना

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा अनोखा पक्षी भी है जो जहरीले सांपों के लिए सीधे मौत का पर्याय माना जाता है इसका नाम है सेक्रेटरी बर्ड, जिसे अपनी शिकार करने की अविश्वसनीय तकनीक और शक्तिशाली लात के लिए जाना जाता है। यह पक्षी अफ्रीका के विशाल सवाना क्षेत्रों में पाया जाता है और वहां के जहरीले सांपों का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जिससे सांप भी इसे देखते ही कांपने लगते हैं। सेक्रेटरी बर्ड का वैज्ञानिक नाम सागीटारियस सेरपेटारियस है। यह लंबी टांगों वाला, गरुड़ जैसा दिखने वाला एक विशाल शिकारी पक्षी है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह उड़ने की बजाय ज्यादातर जमीन पर चलकर ही शिकार करता है और अपने शिकार की तलाश में लंबी दूरी तय कर सकता है। जब इसे कोई सांप दिखता है तो यह अपने विशाल पंख फैलाकर सांप को भड़काता और डराता है। सांप जैसे ही फन फैलाकर हमला करने की कोशिश करता है, सेक्रेटरी बर्ड अपनी तेज और अविश्वसनीय रूप से ताकतवर लात से उस पर बिजली की गति से हमला कर देता है। इसकी लात इतनी शक्तिशाली होती है कि सांप का सिर एक ही वार में कुचल जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसकी लात का दबाव इतना अधिक होता है कि यह सांप की खोपड़ी को तोड़ने के लिए जितनी शक्ति की जरूरत होती है, उससे लगभग 5 गुना ज्यादा होती है। यह इतना सटीक और तेज हमला करता है कि सांप को फन फैलाने या जवाबी हमला करने का मौका ही नहीं मिलता। सेक्रेटरी बर्ड मुख्य रूप से जहरीले सांपों को ही निशाना बनाता है। कोबरा, वाइपर और अन्य जहरीले सांप इसके पसंदीदा शिकार हैं। हैरानी की बात यह है कि यह सांप के जहर से भी नहीं डरता। अगर सांप काट भी ले तो भी यह पक्षी ज्यादातर मामलों में बच जाता है, जो इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती को दर्शाता है।

इस पक्षी का नाम सेक्रेटरी' इसलिए पड़ा क्योंकि इसके सिर पर पंखों का एक गुच्छा होता है जो पुराने जमाने के सेक्रेटरी के सिर पर लगाए जाने वाले पेन की तरह दिखता है। यह एक लंबा-चौड़ा पक्षी है, जिसकी ऊंचाई करीब 1.3 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 4 किलोग्राम तक होता है। इसकी टांगें इतनी मजबूत और लंबी होती हैं कि यह छोटे जानवरों और सांपों को आसानी से मार सकता है। सांप का शिकार करने के लिए ये एक खास रणनीति अपनाता है: सबसे पहले, सांप को देखते ही ये जमीन पर तेजी से दौड़ता है। फिर अपने पंख फैलाकर सांप का ध्यान भटकाता है और उसे भ्रमित करता है।

अगले साल भारत जा सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संकेत अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिया है, जिन्होंने बताया कि इस उच्च-स्तरीय यात्रा की दिशा में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यदि यह दौरा होता है, तो यह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली भारत यात्रा होगी, जो दोनों देशों के बीच मजबूत होते रणनीतिक संबंधों को और गति प्रदान करेगी, साथ ही वैश्विक मंच पर उनकी साझेदारी को भी रेखांकित करेगी। वाशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका संबंधों पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री रुबियो ने रेखांकित किया कि दोनों देशों के रिश्ते इस समय अपने शानदार दौर में हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में संपन्न हुए जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहद सकारात्मक और उपयोगी मुलाकात हुई थी, जिसने द्विपक्षीय सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। रुबियो ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील अब अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा और व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रुबियो ने कहा, हम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बस कुछ ही कदम दूर हैं।

तीस्ता प्रोजेक्ट पर चीन ने कहा- हमें तीसरे देश से मतलब नहीं

बीजिंग

बांग्लादेश के साथ बंदरगाह विकास और तीस्ता जल प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बाद, चीन ने यह स्पष्ट किया है कि उसका यह सहयोग किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के उद्देश्य से नहीं है। चीन का यह बयान स्पष्ट तौर पर भारत की ओर इशारा करता है, जो बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती निकटता को अपनी रणनीतिक चिंताओं के साथ देख रहा है।

हाल ही में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत के बजाय चीन को चुना, जिसने कूटनीतिक हलकों में काफी चर्चा बटोरी। उनकी इस यात्रा के दौरान चीनी जल संसाधन मंत्री ली गुओयिंग के साथ बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों ने तीस्ता नदी प्रबंधन और अन्य नदी परियोजनाओं पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।

तीस्ता नदी प्रबंधन में चीन की भागीदारी को भारत रणनीतिक महत्व के साथ देखता है, क्योंकि यह नदी पूर्वी हिमालय से निकलकर सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में यह लाखों लोगों के लिए सिंचाई और आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तीस्ता नदी बेसिन भारत के अत्यंत संवेदनशील सिलीगुड़ी गलियारे के निकट स्थित

है, जो भारतीय मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाली मात्र 22 किलोमीटर चौड़ी भूमि पट्टी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने नई दिल्ली की संभावित चिंताओं संबंधी प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि तीस्ता नदी के व्यापक प्रबंधन और पुनर्वास की परियोजना बांग्लादेश के लिए जनकल्याण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बिना यह भी स्पष्ट किया कि चीन इस परियोजना को समर्थन देने के लिए हरसंभव मदद करने को तैयार है, लेकिन चीन-बांग्लादेश सहयोग किसी तीसरे पक्ष को लक्ष्य बनाकर नहीं किया जा रहा है और यह किसी तीसरे पक्ष के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। यह कथन चीन की ओर से भारत को एक कूटनीतिक संदेश माना जा रहा है। चीनी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बांग्लादेश शी जिनपिंग की वैश्विक पहलों का पूर्ण समर्थन करता है और अंतरराष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मामलों में चीन के साथ समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। इसके अलावा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता महदी अमीन ने दोनों शीर्ष नेताओं की वार्ता पर जानकारी देते हुए बताया कि चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के आधुनिकीकरण में चीन के सहयोग पर भी चर्चा हुई। अमीन ने बिना किसी देश का नाम लिए कहा, हम इन बंदरगाहों को क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कैसे विकसित किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहते हैं, जिससे न केवल बांग्लादेश, बल्कि अन्य देशों को भी लाभ मिल सके। यह चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के तहत बंदरगाहों तक अपनी पहुंच मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। बांग्लादेश की रिपोर्ट बीएसएस के अनुसार, अमीन ने यह भी बताया कि पहली बार बांग्लादेश और चीन के बीच विदेश तथा रक्षा मामलों को शामिल करते हुए संवाद तंत्र पर सहमति बनी है। इसमें दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि भविष्य में नियमित संवाद करेंगे, जिसके तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक मोर्चे पर भी सहयोग बढ़ा है, क्योंकि बांग्लादेश की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के साथ मंदारिन भाषा को तीसरी भाषा के रूप में प्राथमिकता दी जा रही है।

पाक का दोहरा चेहरा : शोएब के भाई के जनाजे में आतंकी पहुंचे

इस्लामाबाद

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के बड़े भाई शाहिद अख्तर के जनाजे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके कथित राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से जुड़े कई प्रमुख व्यक्तियों की उपस्थिति का दावा किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर दोहरे मापदंडों पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना इस्लामाबाद के कब्रिस्तान में हुई थी, जहां शाहिद अख्तर के नमाज-ए-जनाजा में पीएमएमएल के अध्यक्ष इनाम-उर-रहमान और अन्य कार्यकर्ताओं को स्पष्ट रूप से देखा गया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को पीएमएमएल के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी साझा किया गया था, जिससे इसकी प्रामाणिकता और भी पुष्ट होती है।

इनाम-उर-रहमान का नाम पहले भी विवादों

में रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादी हाफिज सईद के राजनीतिक मोर्चे के रूप में देखा जाता रहा है। सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ तस्वीरों में इनाम-उर-रहमान को पहलगाम हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ भी दिखाया गया है, जो इन संगठनों के गहरे संबंधों को उजागर करता है। इन सबके बीच, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज़ सादिक का भी शोएब अख्तर के घर जाकर परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना उल्लेखनीय है। हालांकि स्पीकर की उपस्थिति प्रोटोकाल का हिस्सा हो सकती है, लेकिन एक ही कार्यक्रम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े लोगों और देश के शीर्ष राजनीतिक व्यक्ति की मौजूदगी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच पाकिस्तान की साख पर फिर से प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

जनाजे में कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े लोगों की खुलेआम मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन विभिन्न नामों और मंचों के माध्यम से अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह आतंकवादियों को अपनी धरती पर सुरक्षित पनाहगाह देता है और उनके नेटवर्क को फलने-फूलने का मौका देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को बार-बार ग्रे लिस्ट में डाले जाने का एक बड़ा कारण भी यही रहा है कि वह मनी लान्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण पर लगाम लगाने में असफल रहा है।

ऐसे में, किसी हाई-प्रोफाइल व्यक्ति के जनाजे में इन प्रतिबंधित समूहों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बेरोकटोक उपस्थिति, पाकिस्तान सरकार और उसकी एजेंसियों की प्रतिबद्धता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। यह घटना एक बार फिर पाकिस्तान के उस टेरर लव को बेनकाब करती है, जहाँ आतंकी समूह कथित रूप से समाज के भीतर अपनी जड़ें जमा चुके हैं और राजनीतिक गतिविधियों में भी संलिप्त पाए जाते हैं। यह स्थिति वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए एक गंभीर चुनौती है और पाकिस्तान पर अपनी ज़मीन से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव को और बढ़ाएगी।